Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme to small towns with population less than 20,000 in 1981 consus for implementation as per Rural Water Supply norms.

(b) and (c) In June, 1988, the State Government of Madhya Pra-Pradesh had forwarded a proposal for inclusion of Pachore Urban Water Supply at a cost of Rs. 143·85 lakhs under ARWSP. This scheme was returned to the State Government in July, 1988 as at that time no decision had been taken for extension of ARWSP to small towns with population less than 20,000 (1981 census).

मध्य प्रदेश को सूखाग्रस्त जिलों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जानें वाली धनराशि

1232. **श्रीमती रत्न कुमारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में रायपुर और रीवा डिविजनों में सूखा-ग्रस्त जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने हेतु वर्ष 1988–89 और 1989–90 के दौरान, मदवार, कितनी धनराशि की मांग की थी तथा रोजगार, पेय जल और पोषाहार की व्यवस्था, चारे तथा स्वास्थ्य रक्षा संबंधी कार्यक्रमों के लिये कितनी धनराशि की मांग की है तथा केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि मंजूर की और वास्तव में दी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : मध्य प्रदेश सरकार ने दो ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं, जिनमें सूखा राहत के लिये कुल 88.03 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी गयी है। मांगी गई सहायता का ब्योरा विवरण में दे दिया गया है (नीचे देखिए)। राज्य सरकार को सूखा राहत के लिये जून, 1989 तक 14.01 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकार की गयी है। राज्य सरकार को साधनोपाय पेशगी के रूप में 10.00 करोड़ रुपये की राशि भी निर्मुक्त की गय थी।

विवरण

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूखा राहत के लिये मांगी गयी मदवार सहायता

क्रम संख्या	मद	निम्न के लिये मांगी गयी सहायता		
		1988–89 (नवम्बर, 88 से मार्च, 16 1989 तक)	1989–90 (अप्रैल से जून 1990 तक)	कुल
1		2		3
1.	रोजगार का सृजन . . .	2533.01	2029.50	4562.51
2.	प्रादान संबंधी राहसहायता . .	359.46	721.22	1080.68

1	2		3
3. जल परिवहन सहित पेयजल का अभाव .	322.10	820.30	1142.40
4. पोषण	429.44	301.17	730.61
5. जन स्वास्थ्य	286.29	280.87	567.16
6. निःशुल्क राहत . . .	9.70	9.70	19.40
7. चारा संबंधी अभाव तथा पशु स्वास्थ्य .	215.30	457.00	672.30
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण .	28.30	—	28.30
कुल	4183.60	4619.76	8803.36

दूरदर्शन में पुरुष और महिला उद्घोषक

1233. **श्री संतोष बागड़ोदिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन में पुरुष तथा महिला उद्घोषकों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन में अधिकतर उद्घोषणायें महिला उद्घोषकों द्वारा की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० तिवारी) : (क) तीन नियमित महिला प्रस्तुतीकरण उद्घोषकों के अलावा, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के पैनल में 15 कैजुअल उद्घोषक/कम्पीयर हैं, जिनमें से 12 महिलायें हैं ।

(ख) और (ग) चूंकि महिला उद्घोषक अधिक है, अतः अधिकांश उद्घोषणायें उनके द्वारा की जाती हैं।

राजस्थान में आपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति) के अधीन सहकारी समितियां

1234. **श्री संतोष बागड़ोदिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में "आपरेशन फ्लड" (श्वेत क्रांति) के अधीन कितनी सहकारी समितियां स्थापित की गयी हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन समितियों के सदस्यों की संख्या कितनी रही;

(ग) क्या दूध की बिक्री से किसानों की आय में कोई वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) पिछले तीन